

problems and to the need of heart operations of children in Andhra Pradesh.

Sir, there is a very serious social and health concern in Andhra Pradesh. Thousands of...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. honumentha Rao, whet yon are reading is not in the text here. ...*(Interruptions/)*... You have to read only the text that you have given to the hon. Chairman.

SHRI V. HANUMANTHA RAO: AH right, Sir. Each operation costs about...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You start from The State Government does not have...'. You have to read what you have given to the Chairman. ...*(Interruptions/)*...

SHRI V. HANUMANTHA RAO: The State Government does not have the resources to fund the critical heart operations of children who are waiting for months for heart operations. Many children are also dying white they wait for heart operations in Andhra Pradesh. I request the Central Government to pay attention to this critical problem as parents are agitating for medical help.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is all.

SHRI V. HANUMANTHA RAO: That's all?

श्री उपसभापति: इतना ही अप्रुव हुआ है।...*(व्यवधान)*...

SHRI V. HANUMANTHA RAO: No, Sir. I want to say something. What is this, Sir? I want the Central Government to intervene in this matter. There is no money in Andhra Pradesh. ...*(Interaptions/)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: -Shri Kripal Parmer.

**Demand to make it mandatory to print Pesticide contents on cold
dalik Bottles**

श्री कृपाल परभार(हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विक्रय किए जा रहे शीतल पेयो (कोल्ड ड्रिंक्स) में मानक से 50 प्रतिशत अधिक जहरीले रासायन और कीटनाशकों का पाया जाना विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र, सेटर फार साइंस एंड एनवायरन्मेंट (सीएसई) की प्रदूषण निगरानी प्रयोगशाला की एक टीम ने विश्वस्तरीय मान्य जांच प्रक्रियाओं के अनुसार जांच करने पर

प्रमाणित किया था। सरकार ने इससे चिंतित होकर एक संयुक्त संसदीय जांच समिति (जेपीसी) का गठन किया था।

संसदीय जांच समिति ने दो वर्ष तक विभिन्न बहुराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कम्पनियों के प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों के साक्ष्य लेकर सर्वसम्मति से अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया। वह प्रतिवेदन भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के शीतल पेयों में स्वीकृत मापदंडों से अधिक जहरीले रसायनों एवं कीटनाशकों की उपस्थिति को प्रमाणित करता था और कुल मिलाकर जांच प्रतिवेदन उक्त कम्पनियों के प्रतिकूल था।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सिगरेट के पैकेट एवं शराब की बोतलों पर चेतावनी छपी जाती है कि “इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है” उसी प्रकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा देश में विक्रय किए जा रहे शीतल पेय की बोतलों पर चेतावनी छपा जाना अनिवार्य किया जाए कि “इसमें जहरीले रसायन और कीटनाशी हैं।”

श्री मनोज भट्टाचार्य (पश्चिमी बंगाल): सर, मैं माननीय सदस्य से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री मती सविता शारदा (गुजरात): महोदय, मैं माननीय सदस्य से स्वयं को संबद्ध करती हूँ।

श्री अजय मारू (झारखंड): महोदय, मैं माननीय सदस्य से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश): महोदय, इसी तरह से पैकड जूसिज़ पर भी लिखा होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... बीजेपी के खिलाफ नहीं है। ...**(व्यवधान)**... जूस आप नहीं बना रहे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इसमें कोई विरोध नहीं है। समर्थन ही कर रहा हूँ, क्यों घबरा रहे हैं?

Need for retaining original plan of Rs. 19.00 crores under PMGSY for Andhra Pradesh

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, as my Special Mention relates to the poor rural people of Andhra Pradesh, I draw the attention of the Government of India through this Special Mention. The Government of Andhra Pradesh has been informed that the allocation for Prime Minister's *Grameen Sadak Yojana*, Phase IV for Andhra Pradesh will now be only Rs.90 crores as against the annual allocation of Rs.190 crores. It is injustice to Andhra Pradesh.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please confine to your text.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, Andhra Pradesh is predominantly a rural State with 72.65 per cent of the population living in the rural areas. Out of 67505 habitants, 53986 are connected with roads and 13519 do not